

# EXAM GENIUS

Presents

## ***GENIUS CURRENT AFFAIRS***

**In Bilingual**

**19 February 2026**



UPSC



SSC



BANK



RAILWAY



STATE EXAMS

**Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !**



**Ques: What was the year-on-year (YoY) growth in Currency in Circulation (CiC) in January 2026?**

जनवरी 2026 में प्रचलन में मुद्रा (CiC) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 5.3%
- B) 8.5%
- C) 9.7%
- D) 11.1%
- E) 14.4%

**Answer: Option D**

**Explanation / व्याख्या :**

- Currency in Circulation (CiC) touched a record high of ₹40 lakh crore for the month ending January 2026.
- जनवरी 2026 को समाप्त माह में प्रचलन में मुद्रा (CiC) ₹40 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
- CiC registered a year-on-year growth of 11.1%, significantly higher than 5.3% recorded in January last year.
- CiC में 11.1% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह यह 5.3% थी।
- On a year-to-date (YTD) basis, CiC increased by ₹2.76 lakh crore, which is about 3.11 times higher than the increase during the same period last year.
- वर्ष-से-तारीख (YTD) आधार पर CiC में ₹2.76 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 3.11 गुना अधिक है।
- Despite the rise in cash usage, the cash-to-GDP ratio declined to 11% in FY26 (so far), compared to 14.4% in FY21, indicating deeper financialisation and digital payments penetration.
- नकदी प्रचलन बढ़ने के बावजूद, FY26 (अब तक) में नकद-से-GDP अनुपात घटकर 11% रह गया, जो FY21 में 14.4% था।
- These findings were reported by SBI Research.
- यह आँकड़े SBI Research द्वारा जारी किए गए हैं।





Ques: Who released the latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 (July–September 2025)? Q2 FY 2025–26 (जुलाई–सितंबर 2025) के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया?

- A) Amitabh Kant / अमिताभ कांत
- B) Rajiv Kumar / राजीव कुमार
- C) Suman Bery / सुमन बेरी
- D) Sanjeev Sanyal / संजीव सान्याल
- E) Arvind Panagariya / अरविंद पनगढ़िया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 was released by Suman Bery, Vice-Chairman of NITI Aayog.
- Q2 FY 2025–26 के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
- The report notes that global trade growth has moderated but remains positive, with services trade outperforming goods trade.
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन सकारात्मक बनी हुई है, जहाँ सेवा व्यापार वस्तु व्यापार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- India's trade expansion in Q2 FY26 was driven by export-led momentum, with services and merchandise exports growing by around 8.5%, faster than imports.
- Q2 FY26 में भारत का व्यापार विस्तार निर्यात-आधारित गति से संचालित रहा, जहाँ सेवा और वस्तु निर्यात लगभग 8.5% बढ़े, जो आयात वृद्धि से अधिक था।
- The report highlights India's increasing alignment with regional value chains and new trade corridors.
- रिपोर्ट में क्षेत्रीय वैल्यू चेन और नए व्यापार गलियारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है।
- E-commerce exports, though currently modest, are projected to contribute 20–30% of India's merchandise exports by 2030.
- ई-कॉमर्स निर्यात वर्तमान में सीमित हैं, लेकिन 2030 तक भारत के वस्तु निर्यात में 20–30% योगदान देने का अनुमान है।





**Ques: NPCI extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors attending which event?**

NPCI ने 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए किया?

- A) G20 Summit 2026 / G20 शिखर सम्मेलन 2026
- B) India AI Impact Summit 2026 / इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026
- C) Digital India Conference 2026 / डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2026
- D) Vibrant Gujarat Summit 2026 / वाइब्रेंट गुजरात समिट 2026
- E) World Economic Forum 2026 / वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026

**Answer: Option B**

**Explanation / व्याख्या :**

- National Payments Corporation of India (NPCI) has extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors from 40+ countries.
- National Payments Corporation of India (NPCI) ने 40 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किया है।
- This facility is specifically available for attendees of the India AI Impact Summit 2026, held from 16–20 February 2026 in New Delhi.
- यह सुविधा 16–20 फरवरी 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में भाग लेने वाले आगंतुकों के लिए उपलब्ध है।
- Under this pilot initiative, foreign travellers can make seamless, secure, real-time Person-to-Merchant (P2M) payments using UPI while staying in India.
- इस पायलट पहल के तहत विदेशी यात्री भारत में रहते हुए सहज, सुरक्षित और रियल-टाइम Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान कर सकते हैं।
- The initiative aims to promote digital payments, showcase India's fintech leadership, and enhance convenience for inbound tourists and global delegates.
- इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भारत की फिनटेक क्षमता को प्रदर्शित करना और विदेशी पर्यटकों व वैश्विक प्रतिनिधियों की सुविधा बढ़ाना है।





**Ques: Which company received full WHO approval for the polio vaccine nOPV2?**  
किस कंपनी को पोलियो वैक्सीन nOPV2 के लिए WHO की पूर्ण मंजूरी मिली?

- A) Serum Institute of India / सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
- B) Bharat Biotech / भारत बायोटेक
- C) Biological E Ltd / बायोलॉजिकल ई लिमिटेड
- D) Zydus Lifesciences / ज़ायडस लाइफसाइंसेज़
- E) Panacea Biotec / पैनासिया बायोटेक

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- Biological E Ltd, a Hyderabad-based company, received full approval from the World Health Organization for its novel oral polio vaccine type-2 (nOPV2).
- हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को अपने नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप-2 (nOPV2) के लिए WHO की पूर्ण मंजूरी प्राप्त हुई।
- This approval upgrades the Phase-I clearance granted in June 2024, enabling complete regulatory authorization.
- यह मंजूरी जून 2024 में मिली चरण-I स्वीकृति का उन्नत चरण है।
- With this approval, the company can now manufacture both the drug substance and the final drug product in-house, completing the entire manufacturing chain at a single site.
- अब कंपनी एक ही स्थान पर दवा पदार्थ और अंतिम उत्पाद दोनों का निर्माण कर सकती है, जिससे पूरी निर्माण श्रृंखला पूरी होती है।
- Biological E has already supplied over 700 million doses of nOPV2 globally, supporting polio outbreak response worldwide.
- बायोलॉजिकल ई अब तक वैश्विक स्तर पर 700 मिलियन से अधिक nOPV2 डोज़ की आपूर्ति कर चुकी है।
- nOPV2 is specifically designed for outbreak control of circulating vaccine-derived poliovirus, offering improved genetic stability compared to earlier vaccines.
- nOPV2 को वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस के प्रकोप नियंत्रण के लिए बेहतर आनुवंशिक स्थिरता के साथ विकसित किया गया है।





**Ques: Why is the Ministry of Defence drafting a standardized framework for book-writing by serving and retired Armed Forces personnel?**

रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन हेतु एक मानकीकृत ढांचा क्यों तैयार कर रहा है?

- A) To promote military literature / सैन्य साहित्य को बढ़ावा देने के लिए
- B) To provide financial incentives for veterans / पूर्व सैनिकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए
- C) To address regulatory gaps and national security concerns / नियामकीय खामियों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए
- D) To ban all memoirs by retired officers / सेवानिवृत्त अधिकारियों की सभी आत्मकथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए
- E) To align with international military publishing norms / अंतरराष्ट्रीय सैन्य प्रकाशन मानकों के अनुरूप होने के लिए

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- The Ministry of Defence is drafting a standardized framework for both serving and retired Armed Forces personnel to bridge existing regulatory gaps related to writing and publishing books.
- रक्षा मंत्रालय सेवारत एवं सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन से जुड़े नियामकीय अंतर को पाटने हेतु एक मानकीकृत ढांचा तैयार कर रहा है।
- The move gained attention due to controversy surrounding the unpublished memoir Four Stars of Destiny by former Army Chief Gen. M.M. Naravane (Retd.).
- यह मुद्दा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (सेवानिवृत्त) की अप्रकाशित आत्मकथा Four Stars of Destiny से जुड़े विवाद के बाद चर्चा में आया।

**Legal Grey Area for Retirees | सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कानूनी अस्पष्टता**

- Unlike serving officers, retired Army personnel are not governed by a single consolidated law for literary works.
- सेवारत अधिकारियों के विपरीत, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन पर कोई एकीकृत कानून नहीं है।





- After retirement, they are not strictly bound by the Army Act, 1950 and Army Rules, 1954 for publications.
- सेवानिवृत्ति के बाद वे आर्मी एक्ट, 1950 और आर्मी रूल्स, 1954 के प्रकाशन संबंधी प्रावधानों से सीधे बंधे नहीं रहते।
- However, the Official Secrets Act (OSA), 1923 applies for life, making disclosure of classified or security-sensitive information a criminal offence.
- हालांकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (OSA) आजीवन लागू रहता है, जिसके तहत गोपनीय या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का खुलासा अपराध है।

### Existing Rules for Serving Personnel | सेवारत कर्मियों के लिए नियम

- Serving officers require mandatory prior written permission for any literary or remunerative work.
- सेवारत अधिकारियों को किसी भी साहित्यिक या पारिश्रमिक कार्य के लिए पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होती है।
- Manuscripts undergo a vetting process through the chain of command, up to Army Headquarters or the MoD.
- पांडुलिपियों की कमांड चैन के माध्यम से जांच होती है, जो सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय तक जाती है।

### Precedent from Civil Services | सिविल सेवा से उदाहरण

- The proposal is inspired by the Central Civil Services (Pension) Rules Amendment, 2021.
- यह प्रस्ताव केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम संशोधन, 2021 से प्रेरित है।
- Under this amendment, retired officials from intelligence or security agencies like RAW or IB must obtain prior government clearance before publishing sensitive material.
- इस संशोधन के तहत RAW या IB जैसी खुफिया एजेंसियों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होती है।
- Unauthorized disclosure can lead to withholding or withdrawal of pension as a penalty.
- अनधिकृत खुलासे पर पेंशन रोके जाने या वापस लेने का प्रावधान है।





**Ques: Which two institutions signed an MoU to promote science communication and evidence-based science policy research in India?**

भारत में विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) CSIR & NITI Aayog / सीएसआईआर और नीति आयोग
- B) DST & ICMR / डीएसटी और आईसीएमआर
- C) Indian National Science Academy & National Institute of Science Communication and Policy Research / भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान
- D) DBT & AIIMS / डीबीटी और एम्स
- E) UGC & NCERT / यूजीसी और एनसीईआरटी

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- Indian National Science Academy and National Institute of Science Communication and Policy Research signed a Memorandum of Understanding (MoU) to promote collaborative activities in science communication and evidence-based science policy research.
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The partnership aims to strengthen evidence-based policymaking in India by connecting scientific research with policy formulation.
- यह साझेदारी भारत में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है।
- The Union Budget (February 2026) allocated approximately ₹6,710.61 crore to CSIR, supporting operational costs for institutes like NIScPR to undertake such collaborations.
- फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में CSIR को लगभग ₹6,710.61 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे NIScPR जैसे संस्थानों को इस प्रकार की साझेदारियाँ करने में सहायता मिलेगी।

**About Indian National Science Academy (INSA) :**



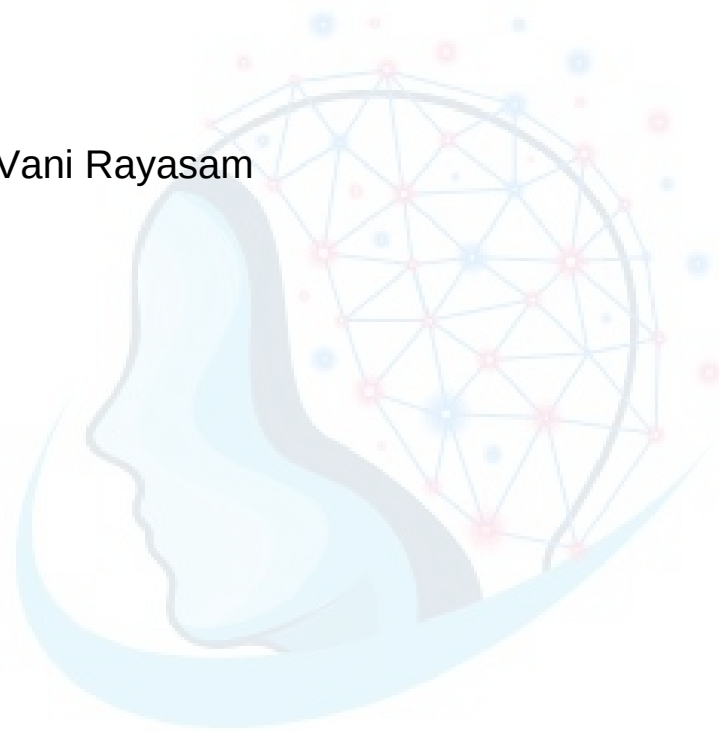


hed : 1935

- HQ : New Delhi
- President : Prof. Shekhar C. Mande

### About CSIR-National Institute of Science Communication and Policy Research (NIScPR) :

- Established : 2021
- HQ : New Delhi
- Director : Dr. Geetha Vani Rayasam



EXAM  
Genius





**Ques: What was a key outcome of the recent India–France bilateral meeting?**

हालिया भारत–फ्रांस द्विपक्षीय बैठक का एक प्रमुख परिणाम क्या था?

- A) Signing of a new climate treaty / नए जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर  
B) Amendment of the Double Taxation Avoidance Agreement and launch of 'Year of Innovation' /  
दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन और 'Year of Innovation' की शुरुआत  
C) Launch of a joint space mission / संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत  
D) Establishment of a common currency / साझा मुद्रा की स्थापना  
E) Withdrawal from defence cooperation / रक्षा सहयोग से हटना

**Answer: Option B**

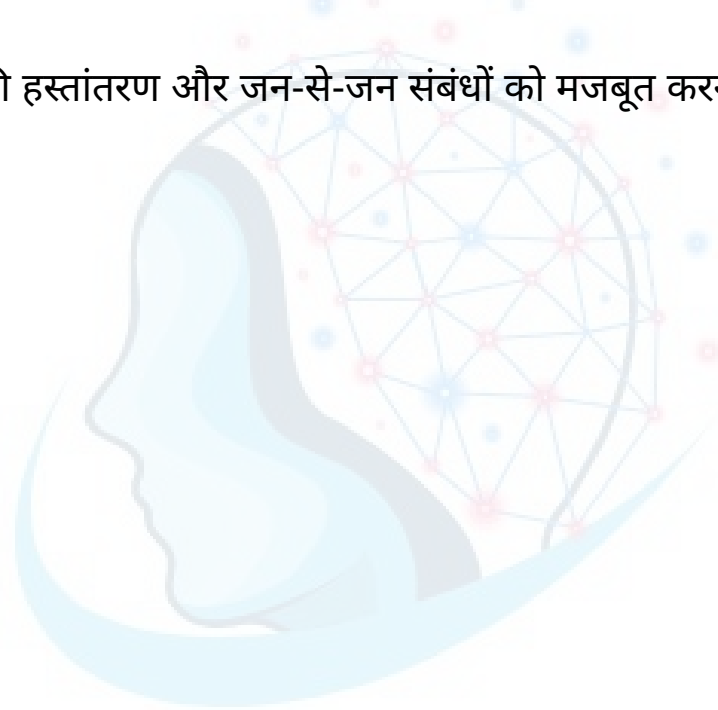
**Explanation / व्याख्या :**

- India and France amended the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) to boost bilateral trade and investments.
- भारत और फ्रांस ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए DTAA में संशोधन किया।
- Narendra Modi and Emmanuel Macron launched the 'India–France Year of Innovation'.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष' की शुरुआत की।
- The initiative will focus on Artificial Intelligence (AI), digital technologies, and start-ups.
- यह पहल AI, डिजिटल तकनीकों और स्टार्ट-अप्स पर केंद्रित होगी।
- Both leaders virtually inaugurated the Tata–Airbus H125 helicopter final assembly line in Karnataka.
- दोनों नेताओं ने कर्नाटक में टाटा–एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- Multiple agreements were signed covering defence, civil nuclear cooperation, critical minerals, health, and counter-terrorism.
- रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य और आतंकवाद-रोधी सहयोग सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
- A joint venture between Bharat Electronics Ltd and Safran for HAMMER missile production was announced.





- BEL और Safran के बीच HAMMER मिसाइल उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई।
- New initiatives include an Indo-French Centre for AI (Health), a Centre of Digital Science & Technology, and a National Centre of Excellence for Skilling in Aeronautics.
- नई पहलों में AI (स्वास्थ्य) के लिए इंडो-फ्रेंच केंद्र, डिजिटल साइंस एवं टेक्नोलॉजी केंद्र, और एरोनॉटिक्स में स्किलिंग हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।
- France reiterated support for technology transfer to India and for strengthening people-to-people ties.
- फ्रांस ने भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जन-से-जन संबंधों को मजबूत करने के समर्थन को दोहराया।



EXAM  
Genius





**Ques: According to the report analysing India's electricity transition under the Current Policy Scenario (CPS) and Net Zero Scenario (NZS), what share of final energy consumption is projected to come from electricity under the NZS by 2070?**

CPS और NZS (2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप) के तहत भारत के बिजली संक्रमण का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट के अनुसार, 2070 तक NZS में अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी कितनी होने का अनुमान है?

- A) 30%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 60%
- E) 75%

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The report analyses India's electricity transition under two scenarios: the Current Policy Scenario (CPS) and the Net Zero Scenario (NZS), aligned with India's 2070 Net Zero commitment.
- रिपोर्ट भारत के बिजली संक्रमण का विश्लेषण दो परिदृश्यों के तहत करती है: करंट पॉलिसी सीनारियो (CPS) और नेट ज़ीरो सीनारियो (NZS), जो भारत के 2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप है।
- The power sector accounted for 39.4% of India's total greenhouse gas (GHG) emissions in 2020, making it the single largest source of emissions.
- वर्ष 2020 में भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बिजली क्षेत्र की हिस्सेदारी 39.4% थी, जिससे यह सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत बन गया।
- Under electrification-led demand growth, electricity is expected to become the dominant energy carrier.
- विद्युतीकरण-आधारित मांग वृद्धि के तहत, बिजली के प्रमुख ऊर्जा वाहक बनने की उम्मीद है।
- The share of electricity in final energy consumption is projected at 40% under CPS and 60% under NZS by 2070.
- अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी CPS के तहत 40% और NZS के तहत 2070 तक 60% होने का अनुमान है।





- Total installed power capacity is expected to multiply 9–14 times by 2070, with renewables contributing 90–93% of total capacity, led mainly by solar PV and wind energy.
- 2070 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता के 9–14 गुना बढ़ने की संभावना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 90–93% होगी, और इसमें सोलर पीवी व पवन ऊर्जा प्रमुख होंगी।
- To support a renewables-heavy grid, strong storage and flexibility measures will be required, including up to 3,000 GW of battery storage and around 160 GW of pumped hydro storage by 2070.
- नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड को संतुलित रखने के लिए 2070 तक लगभग 3,000 GW बैटरी स्टोरेज और लगभग 160 GW पम्पड हाइड्रो स्टोरेज की आवश्यकता होगी।
- Nuclear energy is expected to play a key role as firm power, with nuclear capacity projected to rise from 8.8 GW to over 300 GW by 2070.
- परमाणु ऊर्जा को स्थिर (फर्म) बिजली स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसकी क्षमता 8.8 GW से बढ़कर 2070 तक 300 GW से अधिक हो सकती है।

EXAM  
Genius





**Ques: Who was named BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025?**  
BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025 के रूप में किसे चुना गया?

- A) Harmanpreet Kaur / हरमनप्रीत कौर
- B) PV Sindhu / पीवी सिंधु
- C) Smriti Mandhana / स्मृति मंधाना
- D) Mirabai Chanu / मीराबाई चानू
- E) Nikhat Zareen / निकहत जरीन

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- Smriti Mandhana, Vice-Captain of the Indian Women's Cricket Team, was named BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025.
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025 चुना गया।
- The award recognizes outstanding achievements of Indian women athletes across various sports.
- यह पुरस्कार विभिन्न खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है।
- The award ceremony was organized by the BBC to celebrate excellence in Indian women's sports.
- यह पुरस्कार समारोह BBC द्वारा भारतीय महिला खेलों में उत्कृष्टता के सम्मान हेतु आयोजित किया गया।
- Smriti Mandhana is widely known for her consistent performances and significant contributions to Indian women's cricket at the international level.
- स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट में अपने निरंतर प्रदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं।





**Ques: The first national call for the BIRAC–RDI Fund was announced under which broader Government of India initiative? BIRAC–RDI फंड के लिए पहली राष्ट्रीय कॉल भारत सरकार की किस व्यापक पहल के अंतर्गत घोषित की गई?**

- A) National Biotechnology Development Programme / राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
- B) Startup India Mission / स्टार्टअप इंडिया मिशन
- C) Research, Development and Innovation (RDI) Initiative / अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) पहल
- D) Digital India Programme / डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- E) Make in India Initiative / मेक इन इंडिया पहल

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Dr. Jitendra Singh announced the first national call for the BIRAC–RDI Fund under the Government of India's ₹1 lakh crore Research, Development and Innovation (RDI) initiative.
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार की ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) पहल के अंतर्गत BIRAC–RDI फंड के लिए पहली राष्ट्रीय कॉल की घोषणा की।
- The BIRAC–RDI Fund operates under the institutional framework of the Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) and the Anusandhan National Research Foundation (ANRF).
- BIRAC–RDI फंड, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के संस्थागत ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है।
- The fund is anchored by the Department of Science and Technology (DST).
- यह फंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा एंकर किया गया है।
- Out of the total ₹1 lakh crore RDI corpus, BIRAC has been allocated ₹2,000 crore initially for up to five years.
- कुल ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष में से BIRAC को प्रारंभिक रूप से पाँच वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- The fund provides support through equity, convertible instruments, and long-term debt.
- यह फंड इक्विटी, परिवर्तनीय उपकरणों और दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।





- It supports innovations from Technology Readiness Level (TRL)-4 (validation stage) to TRL-9 (commercial deployment stage).
- यह फंड प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL)-4 (सत्यापन चरण) से लेकर TRL-9 (व्यावसायिक तैनाती चरण) तक के नवाचारों को समर्थन देता है।
- India's bioeconomy has grown from \$28 billion in 2012 to \$165.7 billion in 2024, with a target of \$300 billion by 2030 and \$1 trillion by 2047.
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2012 में \$28 बिलियन से बढ़कर 2024 में \$165.7 बिलियन हो गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक \$300 बिलियन और 2047 तक \$1 ट्रिलियन है।
- The number of biotech startups has increased from around 50 in 2014 to over 11,000 today, indicating rapid ecosystem expansion.
- जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग 50 से बढ़कर आज 11,000 से अधिक हो गई है, जो तेज़ी से विकसित होते इकोसिस्टम को दर्शाता है।

EXAM  
Genius





**Ques: What is the primary purpose of Bharat-VISTAAR launched by the Government of India?**

भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत-विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Direct financial subsidies / प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी
- B) AI-based multilingual agricultural information / AI आधारित बहुभाषी कृषि जानकारी
- C) Free farm equipment / मुफ्त कृषि उपकरण
- D) Crop insurance compensation / फसल बीमा मुआवजा
- E) Online market trading platform / ऑनलाइन बाजार व्यापार मंच

**Answer: Option B**

**Explanation / व्याख्या :**

- The Government of India has launched Bharat-VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources), an AI-powered multilingual digital tool designed especially for farmers.
- भारत सरकार ने भारत-विस्तार (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए एक AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल टूल है।
- The platform provides farmers with agricultural and scheme-related information in their own language through mobile phones or even a simple voice call, ensuring inclusivity.
- यह प्लेटफॉर्म किसानों को मोबाइल या साधारण फोन कॉल के माध्यम से उनकी मातृभाषा में कृषि एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- Farmers can access details of 10 major Central Government schemes, including PM-KISAN, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and Kisan Credit Card (KCC).
- किसान 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- The interface and audio content of Bharat-VISTAAR will be available in 22 से अधिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं to bridge the digital and language divide.
- भारत-विस्तार का इंटरफेस और ऑडियो सामग्री 22+ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे डिजिटल और भाषाई अंतर कम होगा।
- The initiative was announced in the Union Budget 2026–27 with a dedicated allocation of ₹150 crore, highlighting the government's focus on technology-driven





**Ques: Which Indian company received a general licence from the United States government to import Venezuelan crude oil without violating US sanctions?**

किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना वेनेजुएला का कच्चा तेल आयात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से सामान्य लाइसेंस प्राप्त हुआ?

- A) Indian Oil Corporation / इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- B) ONGC Videsh Limited / ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
- C) Bharat Petroleum Corporation Limited / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D) Reliance Industries Limited / रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- E) Hindustan Petroleum Corporation Limited / हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- Reliance Industries Limited (RIL) received a general licence from the United States government to purchase crude oil from Venezuela.
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने के लिए सामान्य लाइसेंस प्राप्त हुआ।
- This licence allows RIL to directly import Venezuelan crude oil without violating US sanctions.
- यह लाइसेंस रिलायंस को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने की अनुमति देता है।
- RIL operates the Jamnagar Refinery Complex in Gujarat, which is the world's largest and most complex single-site refinery.
- रिलायंस गुजरात में जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल सिंगल-साइट रिफाइनरी है।
- The Jamnagar refinery has a significant advantage as it is capable of processing heavy crude and high-sulphur (sour) crude oil.
- जामनगर रिफाइनरी की बड़ी विशेषता यह है कि यह भारी कच्चे तेल और उच्च सल्फर (सॉर) कच्चे तेल को भी प्रोसेस करने में सक्षम है।





**Ques: Where did six-year-old environmental advocate Roohi Mohazzab deliver her keynote address during GCE 2026?**

GCE 2026 के दौरान 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रूही मोहज्ज़ब ने अपना मुख्य भाषण कहाँ दिया?

- A) New York, USA / न्यूयॉर्क, अमेरिका
- B) Geneva, Switzerland / जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- C) Bangkok, Thailand / बैंकॉक, थाईलैंड
- D) Paris, France / पेरिस, फ्रांस
- E) Nairobi, Kenya / नैरोबी, केन्या

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- Roohi Mohazzab, a six-year-old environmental advocate from Kerala, delivered a keynote address at the UN Asia-Pacific Headquarters in Bangkok, Thailand.
- केरल की 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रूही मोहज्ज़ब ने बैंकॉक, थाईलैंड स्थित UN एशिया-प्रशांत मुख्यालय में मुख्य भाषण दिया।
- She spoke during the Global Conference on Education for a Sustainable Future (GCE 2026).
- उन्होंने Global Conference on Education for a Sustainable Future (GCE 2026) के दौरान संबोधन दिया।
- Roohi was honoured with the prestigious SDG Impact Award at the UN Asia-Pacific Headquarters.
- रूही को UN एशिया-प्रशांत मुख्यालय में प्रतिष्ठित SDG Impact Award से सम्मानित किया गया।
- Her recognition highlights the importance of young voices in sustainability, climate action, and global awareness.
- उनका यह सम्मान सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक जागरूकता में युवा आवाज़ों की भूमिका को रेखांकित करता है।





**Ques: Which Indian Major Port became the first to receive the IGBC Platinum Rating for its Administration Building?**

भारत का कौन-सा प्रमुख बंदरगाह अपने प्रशासनिक भवन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बना?

- A) Jawaharlal Nehru Port / जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
- B) Chennai Port / चेन्नई पोर्ट
- C) Paradip Port / पारादीप पोर्ट
- D) V.O. Chidambaranar Port / वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट
- E) Cochin Port / कोचीन पोर्ट

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या :**

- V.O. Chidambaranar Port Authority has become India's first Major Port to receive the prestigious IGBC Platinum Rating, the highest certification awarded by the Indian Green Building Council (IGBC).
- वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण IGBC द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है।
- The Administration Building follows the Port Authority's Green Policy and waste management plan, reinforcing its commitment to sustainability.
- प्रशासनिक भवन पोर्ट प्राधिकरण की ग्रीन नीति और अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अनुरूप बनाया गया है, जो सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- The building is equipped with rooftop solar panels and a high Solar Reflectance Index (SRI) reflective roof coating, helping reduce the Urban Heat Island effect and improve overall energy efficiency.
- भवन में रूफटॉप सोलर पैनल और उच्च SRI रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग लगाई गई है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कम होता है और ऊर्जा दक्षता बढ़ती है।
- The port has also received Shunya and Shunya Plus certifications from the Bureau of Energy Efficiency (BEE) under the Ministry of Power, Government of India.
- यह बंदरगाह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) से शून्य और शून्य प्लस प्रमाणन भी प्राप्त कर चुका है।





## Top 3 Green Award Recipients (2025–2026) | शीर्ष ग्रीन अवॉर्ड प्राप्तकर्ता

- V.O. Chidambaranar Port – IGBC Platinum | Shunya Plus
  - First Major Port in India to run its administration building on 100% renewable energy.
  - प्रशासनिक भवन को 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह।
- Bank of Baroda (Apex Academy) – IGBC Platinum | Shunya
  - Awarded for its state-of-the-art sustainable campus in Ahmedabad (Dec 2025).
  - अहमदाबाद में अत्याधुनिक सतत कैंपस के लिए सम्मानित।
- The Oterra Hotel, Bengaluru – IGBC Platinum | Shunya
  - Recognized as the highest-rated green existing building in India (Jan 2026).
  - भारत की सबसे उच्च रेटिंग वाली ग्रीन मौजूदा इमारत के रूप में मान्यता।

EXAM  
Genius





**Ques: Who has been sworn in as the new Prime Minister of Bangladesh?**

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?

- A) Sheikh Hasina / शेख हसीना
- B) Khaleda Zia / खालिदा जिया
- C) Tarique Rahman / तारीक रहमान
- D) Muhammad Yunus / मोहम्मद यूनस
- E) Mirza Fakhrul Islam Alamgir / मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर

**Answer: Option C**

**Explanation / व्याख्या :**

- Tarique Rahman, chairman of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), was sworn in as the Prime Minister of Bangladesh.
- BNP के अध्यक्ष तारीक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
- He will head a council of 25 Cabinet Ministers and 24 Ministers of State.
- वे 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व करेंगे।
- The oath of office was administered by Mohammed Shahabuddin, the President of Bangladesh, in Dhaka.
- शपथ ढाका में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन द्वारा दिलाई गई।
- The ceremony followed the parliamentary elections and the transfer of power from the interim government.
- यह शपथ ग्रहण संसदीय चुनावों और अंतरिम सरकार से सत्ता हस्तांतरण के बाद हुआ।
- Around 1,200 domestic and foreign guests attended, including dignitaries from Maldives, Pakistan, and India.
- समारोह में मालदीव, पाकिस्तान और भारत सहित लगभग 1,200 अतिथि शामिल हुए।





**Ques: What is 'EKAM' showcased by the Indian Army?**

भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत 'EKAM' क्या है?

- A) A cyber weapon system / साइबर हथियार प्रणाली
- B) A secure indigenous AI cloud platform (AI-as-a-Service) / एक सुरक्षित स्वदेशी AI क्लाउड प्लेटफॉर्म (AI-as-a-Service)
- C) A drone surveillance system / ड्रोन निगरानी प्रणाली
- D) A satellite communication network / उपग्रह संचार नेटवर्क
- E) A blockchain-based defence payment system / ब्लॉकचेन-आधारित रक्षा भुगतान प्रणाली

**Answer: Option B**

**Explanation / व्याख्या :**

- Indian Army showcased 'EKAM', an indigenous AI-as-a-Service (AlaaS) cloud platform.
- भारतीय सेना ने 'EKAM' नामक स्वदेशी AI-as-a-Service क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया।
- EKAM is a secure and air-gapped platform, specifically designed to protect sensitive military data.
- EKAM एक सुरक्षित और air-gapped प्लेटफॉर्म है, जिसे संवेदनशील सैन्य डेटा की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है।
- The platform focuses on data sovereignty and secure processing of critical information.
- यह प्लेटफॉर्म डेटा संप्रभुता और महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- The initiative reflects the Army's push towards technological self-reliance and AI-enabled defence capabilities.
- यह पहल सेना की तकनीकी आत्मनिर्भरता और AI-सक्षम रक्षा क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





**Ques:** The high-level CSR Conclave on “Leveraging PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) for Farmer Prosperity” was organised by which department under the Government of India? “किसान समृद्धि के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) का लाभ उठाना” विषय पर उच्च स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव भारत सरकार के किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया?

- A) Department of Rural Development / ग्रामीण विकास विभाग
- B) Department of Agriculture & Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- C) Ministry of Panchayati Raj / पंचायती राज मंत्रालय
- D) Department of Food & Public Distribution / खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- E) Ministry of Cooperation / सहकारिता मंत्रालय

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The high-level CSR Conclave was organised by the Department of Agriculture & Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
- यह उच्च स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- The conclave was held in New Delhi in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP) and the Bill & Melinda Gates Foundation.
- यह कॉन्क्लेव नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
- The theme of the conclave was “Leveraging PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) for Farmer Prosperity.”
- कॉन्क्लेव का विषय “किसान समृद्धि के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) का लाभ उठाना” था।
- PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) was launched on 11 October 2025 for a duration of 6 years.
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) को 11 अक्टूबर 2025 को 6 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया।
- The scheme covers 100 districts and is India's first agriculture-exclusive programme.
- यह योजना 100 जिलों को कवर करती है और भारत की पहली केवल कृषि-केन्द्रित योजना है।
- The programme is inspired by NITI Aayog's Aspirational District Programme.





**Ques: Which flagship scheme primarily funds marine conservation initiatives in India, including artificial reefs and financial support to fishers?**

भारत में समुद्री संरक्षण पहलों (कृत्रिम रीफ, मछुआरों को वित्तीय सहायता आदि) को मुख्य रूप से कौन-सी प्रमुख योजना वित्तपोषित करती है?

- A) National Mission for Clean Ganga / राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- B) Blue Economy Policy / ब्लू इकोनॉमी नीति
- C) Sagarmala Programme / सागरमाला कार्यक्रम
- D) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana / प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- E) Coastal Regulation Zone Scheme / तटीय विनियमन क्षेत्र योजना

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या :**

- To ensure oceans remain rich in biodiversity for future generations, the Government of India along with research bodies like Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) is implementing targeted marine conservation strategies, especially for species such as Silver Pomfret.
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए महासागरों की जैव-विविधता बनाए रखने हेतु भारत सरकार और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) जैसे अनुसंधान संस्थान सिल्वर पॉम्फ्रेट जैसी प्रजातियों पर विशेष ध्यान देते हुए संरक्षण रणनीतियाँ लागू कर रहे हैं।
- To prevent “over-cleaning” and overfishing of oceans, mesh-size regulations are enforced so that nets have sufficiently large holes to allow juvenile fish to escape.
- महासागरों में अत्यधिक मछली पकड़ने से रोकने के लिए जाल के जाल-आकार (Mesh-Size) नियम लागू किए गए हैं, जिससे छोटी मछलियाँ बाहर निकल सकें।
- Certain fishing methods are banned, including:
  - Bull/Pair trawling, to protect the ocean floor.
  - LED lights, as they unnaturally attract fish.
- समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु कुछ विधियाँ प्रतिबंधित हैं, जैसे:
  - बुल/पेयर ट्रॉलिंग, जिससे समुद्र तल को नुकसान होता है।
  - LED लाइट्स, क्योंकि ये मछलियों को अस्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं।
- As per the Marine Fish Stock Status Report 2022, 91.1% of India’s marine fish stocks are in healthy condition.





- मरीन फिश स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 91.1% समुद्री मत्स्य भंडार स्वस्थ स्थिति में हैं।
- Funding for conservation initiatives such as artificial reefs and financial aid to fishers is mainly driven by the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, a flagship scheme aimed at transforming India's fisheries sector.
- कृत्रिम रीफ और मछुआरों को वित्तीय सहायता जैसी पहलों का वित्तपोषण मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया जाता है, जो भारत के मत्स्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की प्रमुख योजना है।
- The Silver Pomfret (*Pampus argenteus*), often called the "King of Fish" in South and Southeast Asia, is nutritionally rich and a key focus of conservation efforts.
- सिल्वर पॉम्फ्रेट (*Pampus argenteus*) को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में "मछलियों का राजा" कहा जाता है और यह पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

## Marine Conservation Measures | समुद्री संरक्षण उपाय

- Minimum Legal Size (MLS): Prevents juvenile fishing; fish below a specified size (e.g., 140 mm for Pomfret) cannot be caught.
- न्यूनतम वैधानिक आकार (MLS): छोटी मछलियों के शिकार पर रोक; निर्धारित आकार (जैसे पॉम्फ्रेट के लिए 140 मिमी) से कम मछली नहीं पकड़ी जा सकती।
- State Fish Status: Silver Pomfret is the State Fish of Maharashtra to promote conservation and breeding.
- राज्य मछली दर्जा: प्रजनन संरक्षण के लिए सिल्वर पॉम्फ्रेट महाराष्ट्र की राज्य मछली है।
- Zonal Restrictions: Near-shore areas reserved for traditional fishers; large vessels are restricted.
- क्षेत्रीय प्रतिबंध: तटवर्ती क्षेत्रों को पारंपरिक मछुआरों के लिए आरक्षित किया गया है; बड़े जहाजों पर रोक है।
- Fishing Ban: A 61-day annual ban on both East and West coasts to allow breeding.
- मछली पकड़ने पर प्रतिबंध: प्रजनन के लिए पूर्वी व पश्चिमी तटों पर 61 दिनों का वार्षिक प्रतिबंध।
- Financial Aid: Fishers receive ₹4,500 (₹1,500 contribution + ₹3,000 government subsidy) during ban periods.
- वित्तीय सहायता: प्रतिबंध अवधि में मछुआरों को ₹4,500 (₹1,500 अंशदान + ₹3,000 सरकारी सब्सिडी) मिलती है।
- Artificial Reefs: Man-made structures placed on the sea floor to restore habitats and boost fish populations.
- कृत्रिम रीफ: समुद्र तल पर बनाए गए ढांचे, जो आवास पुनर्स्थापन और मछली आबादी बढ़ाने में सहायक हैं।





## Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana :

- Launched : September 10, 2020
- Nodal Ministry : Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
- Chairperson (Union Minister) : Shri Rajiv Ranjan Singh
- Global Rank : India is the 2nd largest fish producer in the world.
- Agri-GVA Contribution : Fisheries contribute 7.43% to Agriculture GVA.
- Budget FY 2026-27 : ₹2,500 Crore (highest ever allocation for PMMSY).
- Key Sub-Scheme : PM-MKSSY (Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana) - ₹6,000 Crore outlay.
- Goal : Integrated development of 500 reservoirs & Amrit Sarovars



EXAM  
Genius





**Ques: According to India's tech services roadmap aligned with Viksit Bharat@2047, what is the targeted annual revenue size of India's technology services industry by 2035?**

विकसित भारत@2047 के अनुरूप भारत की टेक सर्विसेज रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत की प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग का लक्षित वार्षिक राजस्व कितना है?

- A) \$400–500 billion / 400–500 अरब डॉलर
- B) \$550–650 billion / 550–650 अरब डॉलर
- C) \$650–700 billion / 650–700 अरब डॉलर
- D) \$750–850 billion / 750–850 अरब डॉलर
- E) Above \$1 trillion / 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक

**Answer: Option D**

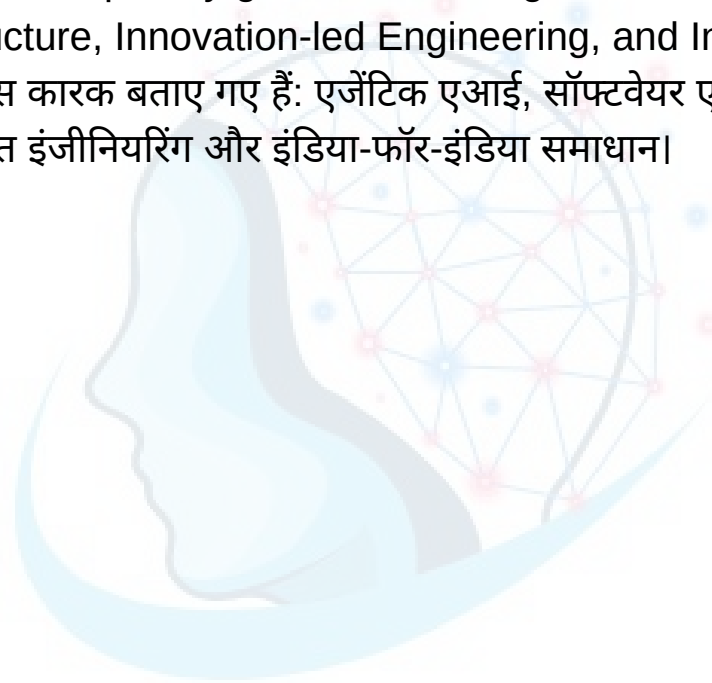
**Explanation | व्याख्या:**

- India's tech services industry comprises companies that design, build, implement, manage, and support technology solutions for global and domestic clients.
- भारत का टेक सर्विसेज उद्योग उन कंपनियों से मिलकर बना है जो वैश्विक और घरेलू ग्राहकों के लिए तकनीकी समाधान डिज़ाइन, निर्माण, कार्यान्वयन और प्रबंधन करती हैं।
- Core segments of the industry include IT services, software development, digital transformation, business process & operations management, and engineering & R&D services.
- इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं: आईटी सेवाएँ, सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल परिवर्तन, बिज़नेस प्रोसेस एवं ऑपरेशंस मैनेजमेंट तथा इंजीनियरिंग एवं R&D सेवाएँ।
- The sector contributes nearly 7% to India's GDP and generates around \$265 billion in annual revenue.
- यह क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 7% का योगदान देता है और लगभग 265 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है।
- India accounts for nearly 20% share in the global tech services market.
- वैश्विक टेक सर्विसेज बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है।
- Under the Viksit Bharat@2047 vision, India aims to scale the tech services industry to \$750–850 billion in annual revenue by 2035 and increase its global market share beyond 25%.





- विकसित भारत@2047 के तहत, भारत का लक्ष्य 2035 तक टेक सर्विसेज उद्योग का वार्षिक राजस्व 750–850 अरब डॉलर तक पहुँचाना और वैश्विक हिस्सेदारी को 25% से अधिक करना है।
- However, current projections indicate a potential revenue shortfall of \$250–300 billion if growth momentum is not accelerated.
- हालांकि, यदि विकास की गति तेज नहीं हुई तो 250–300 अरब डॉलर के राजस्व घाटे की संभावना जताई गई है।
- The roadmap identifies five priority growth levers: Agentic AI, Software & Products (SaaS), Digital Infrastructure, Innovation-led Engineering, and India-for-India solutions.
- रोडमैप में पाँच प्रमुख विकास कारक बताए गए हैं: एजेंटिक एआई, सॉफ्टवेयर एवं उत्पाद (SaaS), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार-आधारित इंजीनियरिंग और इंडिया-फॉर-इंडिया समाधान।



EXAM  
Genius





**Ques: APEDA was established under which Act?**

APEDA की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?

- A) Foreign Trade Act, 1992 / विदेशी व्यापार अधिनियम, 1992
- B) APEDA Act, 1985 / APEDA अधिनियम, 1985
- C) Food Safety Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006
- D) Export Promotion Act, 1980 / निर्यात प्रोत्साहन अधिनियम, 1980
- E) Agricultural Trade Act, 1991 / कृषि व्यापार अधिनियम, 1991

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या :**

- APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) was established under the APEDA Act, 1985.
- APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) की स्थापना APEDA अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
- The Act was passed in December 1985 and came into force on 13 February 1986, marking the beginning of APEDA's statutory role.
- यह अधिनियम दिसंबर 1985 में पारित हुआ और 13 फरवरी 1986 से लागू हुआ।
- APEDA replaced the earlier Processed Food Export Promotion Council (PFEP) to provide a stronger institutional framework for exports.
- APEDA ने Processed Food Export Promotion Council (PFEP) का स्थान लिया।
- It functions under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India.
- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- In FY 2024–25, APEDA contributed USD 28.59 billion out of India's total USD 51.91 billion agricultural exports.
- वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के कुल USD 51.91 बिलियन कृषि निर्यात में से USD 28.59 बिलियन का योगदान APEDA का रहा।
- Over the past decade, India's agricultural exports rose from USD 38.66 billion to USD 51.90 billion, reflecting sustained growth.
- पिछले एक दशक में भारत का कृषि निर्यात USD 38.66 बिलियन से बढ़कर USD 51.90 बिलियन हो गया।





**Ques: Why is the rapid thinning and retreat of the Thwaites Glacier considered a major global concern?**

थ्वाइट्स ग्लेशियर के तेजी से पतले होने और पीछे हटने को वैश्विक चिंता क्यों माना जाता है?

- A) Because it is the coldest glacier in the world / क्योंकि यह दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर है
- B) Because it supports marine biodiversity only / क्योंकि यह केवल समुद्री जैव विविधता को सहारा देता है
- C) Because its collapse could trigger massive global sea-level rise / क्योंकि इसके ढहने से वैश्विक समुद्र-स्तर में भारी वृद्धि हो सकती है
- D) Because it lies entirely on land and has no ocean connection / क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर स्थित है और समुद्र से कोई संबंध नहीं है
- E) Because it is shrinking slower than other Antarctic glaciers / क्योंकि यह अन्य अंटार्कटिक ग्लेशियरों की तुलना में धीमी गति से सिकुड़ रहा है

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- Recent studies show rapid thinning and retreat of the Thwaites Glacier located in West Antarctica.
- हालिया अध्ययनों में थ्वाइट्स ग्लेशियर (पश्चिम अंटार्कटिका) के तेजी से पतले होने और पीछे हटने की पुष्टि हुई है।
- It is one of the world's widest glaciers, with a width of about 120 km.
- यह लगभग 120 किमी चौड़ा है, जो इसे दुनिया के सबसे चौड़े ग्लेशियरों में शामिल करता है।
- The glacier covers an area of nearly 1.9 lakh वर्ग किमी, roughly comparable to Great Britain or the Indian state of Gujarat.
- इसका क्षेत्रफल लगभग 1.9 लाख वर्ग किमी है, जो ग्रेट ब्रिटेन या गुजरात राज्य के बराबर है।
- Thwaites is a fast-moving glacier, meaning its ice reaches the ocean quickly, accelerating ice loss.
- थ्वाइट्स एक तेज़ी से बहने वाला ग्लेशियर है, जिससे बर्फ तेजी से समुद्र में पहुँचती है।
- If Thwaites Glacier collapses, it alone contains enough ice to raise global sea levels by about 0.5 मीटर.
- यदि यह ग्लेशियर ढह गया, तो अकेले इससे ही वैश्विक समुद्र-स्तर लगभग 0.5 मीटर बढ़ सकता है।





**Ques: The Raksha Mantri approved the expansion of the definition of 'family' for which purpose?**

रक्षा मंत्री ने 'परिवार' की परिभाषा के विस्तार को किस उद्देश्य के लिए मंजूरी दी है?

- A) Pension eligibility of Armed Forces personnel / सशस्त्र बल कर्मियों की पेंशन पात्रता
- B) Allotment of Government Accommodation to Service Officers / सेवा अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन
- C) Promotion policy reforms / पदोन्नति नीति में सुधार
- D) Medical benefits under ECHS / ईसीएचएस के तहत चिकित्सा लाभ
- E) Leave and travel concessions / अवकाश और यात्रा रियायतें

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या :**

- The Raksha Mantri has approved a proposal to expand the definition of 'family' for the allotment of Government Accommodation to Service Officers of the Armed Forces.
- रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के सेवा अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन के लिए 'परिवार' की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दी है।
- Core Theme: Social Welfare Reform and Administrative Modernization.
- मुख्य विषय: सामाजिक कल्याण सुधार और प्रशासनिक आधुनिकीकरण।
- The decision aligns with the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, reinforcing the legal obligation of children to care for their parents.
- यह निर्णय Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के अनुरूप है, जो माता-पिता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी को मजबूत करता है।
- The move specifically benefits Single Women Officers who live with and take care of their elderly parents.
- यह कदम विशेष रूप से उन एकल महिला अधिकारियों के लिए लाभकारी है जो अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं।
- Key Changes in Definition | परिभाषा में प्रमुख बदलाव
  - Existing members: Spouse, dependent children, and step-children.
  - मौजूदा सदस्य: जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और सौतेले बच्चे।
  - Added members: Parents, dependent siblings, and legally adopted children.
  - जोड़े गए सदस्य: माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे।





**Ques: Which institute has successfully achieved induced breeding of the Mangrove Clam (*Geloina erosa*)? किस संस्थान ने मैंग्रोव क्लैम (*Geloina erosa*) का कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक किया है?**

- A) ICAR–CIFT, Kochi / आईसीएआर–सीआईएफटी, कोच्चि
- B) ICAR–CMFRI, Kochi / आईसीएआर–सीएमएफआरआई, कोच्चि
- C) CIFRI, Barrackpore / सीआईएफआरआई, बैरकपुर
- D) National Institute of Oceanography, Goa / राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा
- E) Zoological Survey of India, Kolkata / प्राणी सर्वेक्षण भारत, कोलकाता

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The induced breeding of Mangrove Clam (*Geloina erosa*) has been achieved by ICAR–Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI).
- मैंग्रोव क्लैम (*Geloina erosa*) का कृत्रिम प्रजनन आईसीएआर–केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा किया गया है।
- Mangrove clam is commonly known as mud clam.
- मैंग्रोव क्लैम को सामान्यतः मड क्लैम कहा जाता है।
- The scientific name of the mangrove clam is *Geloina erosa* and it belongs to the bivalve group under the phylum Mollusca.
- मैंग्रोव क्लैम का वैज्ञानिक नाम *Geloina erosa* है और यह मोलस्का संघ के द्विपटली (बाइवेल्व) वर्ग से संबंधित है।
- The species is found in mangrove and estuarine ecosystems.
- यह प्रजाति मैंग्रोव और मुहाना (एस्टुअरीन) पारितंत्रों में पाई जाती है।
- It is distributed across South and Southeast Asia. In India, it is commonly found along the western coast.
- इसका वितरण दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर पाई जाती है।
- In parts of Kerala, it is locally known as “Kandal Kakka”.
- केरल के कुछ हिस्सों में इसे स्थानीय रूप से “कंडल कक्का” कहा जाता है।





**Ques: Whose birth anniversary is observed as Antyodaya Diwas in India?**

भारत में अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है?

- A) Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी
- B) Ram Manohar Lohia / राम मनोहर लोहिया
- C) Pandit Deendayal Upadhyaya / पंडित दीनदयाल उपाध्याय
- D) Jayaprakash Narayan / जयप्रकाश नारायण
- E) B. R. Ambedkar / डॉ. बी. आर. अंबेडकर

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या :**

- The Vice-President of India paid tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya on his death anniversary, observed on 11 February 1968.
- भारत के उपराष्ट्रपति ने 11 फरवरी 1968 को उनकी पुण्यतिथि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- He was an Indian politician, philosopher, and ideologue associated with the RSS and Bharatiya Jana Sangh (BJS), the predecessor of the Bharatiya Janata Party (BJP).
- वे एक भारतीय राजनेता, दार्शनिक और RSS तथा भारतीय जनसंघ (BJS) के प्रमुख विचारक थे, जो भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन था।
- His core philosophy was Antyodaya, which focuses on uplifting the last person in society and addressing the needs of the most disadvantaged.
- उनका मूल विचार अंत्योदय था, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है।
- Since 25 September 2014, his birth anniversary has been observed nationwide as Antyodaya Diwas to honor his contributions.
- 25 सितंबर 2014 से उनकी जयंती को देशभर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
- In 2015, the National Rural Livelihood Mission (NRLM) was renamed Deendayal Antyodaya Yojana–NRLM in his honor.
- 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना–NRLM किया गया।
- In 2018, Mughalsarai Junction in Uttar Pradesh was renamed Pandit Deendayal Upadhyaya Junction.
- 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया।

